

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र	RAJASTHAN GAZETTE
	विशेषांक	Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 20, बुधवार, शाके 1942-जून 10, 2020 Jyaistha 20, Wednesday, Saka 1942-June 10, 2020		

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायो के लिए टेन्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, मई 11, 2020

संख्या राविविआ/सचिव/विनियम - 137 विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36वां) की धारा 91 सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

सामान्य

1. लघुशीर्षक, प्रारम्भण तथा विषय-क्षेत्र:

- (1) ये विनियम, "राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सेवा) (छठा संशोधन) विनियम, 2020" कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम, शासकीय राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. (i) विनियम 14(1) में संशोधन:

विद्यमान विनियम 14(1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"यदि राज्य के विद्युत क्षेत्र की कंपनियों और राजकॉम सहित राजस्थान सरकार के आईटी विभाग का नियमित रूप से कोई चयनित कर्मचारी जो आयोग में किसी पद पर तीन साल या उससे अधिक समय तक प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा है और आयोग की सेवाओं का चयन करने हेतु उस पद पर अपने स्थायी समामेलन की इच्छा रखता है, तो इस प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा गठित समिति, पदधारी के सेवा-अभिलेख और कार्यदक्षता, उस श्रेणी में सृजित और रिक्त पदों की कुल संख्या और आयोग के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए उसके दावे पर विचार करेगी। राज्य सरकार के अन्य विभाग/संगठन में नियमित रूप से चयनित कर्मचारियों का समामेलन, जिन्होंने आयोग में तीन साल या उससे अधिक समय तक कार्य किया है, राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् प्रभावी होगा। समामेलन के सभी मामलों में, समामेलित कर्मचारियों को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में नियुक्त किया जायेगा और वे केवल नयी अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के लाभ के लिए पात्र होंगे और पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि जैसे किसी भी अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार नहीं होंगे भले ही वे अपने मूल विभाग में पेंशन लाभ के लिए पात्र थे। तथापि, ऐसे व्यक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

बशर्ते कि सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि के लिए

आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान समामेलन के समय पर राज्य सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार लागू होंगे।

टिप्पणी: जहां नियमों में भर्ती के दोनों तरीके, अर्थात् सीधी भर्ती और पदोन्नति, का प्रावधान हैं, तो समामेलन सीधी भर्ती की स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध किया जायेगा और उसी वर्ष के पदोन्नति कोटा के विरुद्ध पहले से ही चयनित पदोन्नत-व्यक्ति से वरीयता में कनिष्ठ होगा। 100% सीधी भर्ती के मामले में, समामेलित-व्यक्ति सीधे भर्ती वाले व्यक्ति से वरीयता में वरिष्ठ होगा परन्तु 100% पदोन्नति कोटा के मामले में, नियमित पदोन्नत-व्यक्ति समामेलित-व्यक्ति से वरीयता में वरिष्ठ होगा।"

(ii) **विनियम 14(2) में संशोधन:**

विद्यमान विनियम 14(2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"आयोग में समामेलन से पहले ऐसे व्यक्ति द्वारा मूल विभाग/संगठन में की गई सेवा को वेतन निर्धारण, एसीपी (A C P) के प्रयोजनार्थ यथा निरंतर सेवा के रूप में गिना जायेगा। मूल संगठन के अन्तर्गत अर्जित अवकाश की किसी भी शेष राशि को अग्रणीत नहीं किया जायेगा परन्तु मूल संगठन में की गई सेवा के दौरान मातृत्व अवकाश, पैतृक अवकाश, शिशु दत्तक अवकाश, शिशु देखरेख अवकाश, अध्ययन अवकाश इत्यादि के उपभोगित अवकाश को राविविआ के तहत यथा उपभोगित के व्यवहृत किया जायेगा। मूल संगठन के अन्तर्गत पद का अनुभव केवल पदोन्नति के लिए गिना जायेगा, यदि ऐसे अनुभव में किसी वरिष्ठ अधिकारी का अतिक्रमण अन्तर्ग्रस्त नहीं है, सिवाय इसके कि जब ऐसा अतिक्रमण या तो निर्धारित शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं के अभाव के कारण, अयोग्यता या योग्यता द्वारा चयन नहीं होना या संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के व्यक्तिक्रम के कारण था।"

आयोग की आज्ञा से

बी. के. दोसी,

सचिव

RAJASTHAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Jaipur, May 11, 2020

No. RERC/Secy/Regulation-137:-In exercise of the powers conferred on it by Section 91 read with Section-181 of the Electricity Act, 2003, (No.36 of 2003), the Rajasthan Electricity Regulatory Commission after previous publication hereby makes the following regulations, namely: -

GENERAL

1. Short Title, Commencement and Scope:

- i. These Regulations shall be called the "Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Service) (Sixth Amendment) Regulations, 2020".

- ii. These regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

2. (i) Amendment in Regulation 14(1):

The existing Regulation 14(1) shall be replaced as under:

“If a regularly selected employee of the Power Sector Companies of the State and IT Department of Govt. of Rajasthan including RAJCOM working on deputation for a period of atleast three years or more on any post in the Commission desires his permanent absorption on that post, in order to opt for the services of the Commission, the Committee constituted by the Commission for the purpose shall consider his claim keeping in view the record of service and performance of the incumbent, total number of posts created and vacant in that category and overall interest of the Commission. Absorption of employees regularly selected in other departments/organizations of the State Government, who have worked for three years or more in the Commission shall be affected only after approval of the State Government. In all cases of absorption, the absorbed employees shall be appointed in RERC and they shall be eligible for the benefits of New Contributory Pension Scheme (NPS) only and shall not be entitled for any other retirement benefits like pension, gratuity, leave encashment etc. even though they were eligible for pensionary benefits in their parent department. However, such persons shall be governed by the provisions of NPS.

Provided that provisions of Reservation/Roster for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Class, Most Backward class or Economically Weaker Sections etc. for direct recruitment or promotion, as the case may be, shall be applicable as per prevailing policy of the State Government at the time of absorption.

Note: Where both methods of recruitment, i.e. direct recruitment and promotions, are provided in rules, then the absorption shall be made against the clear vacancy of direct recruitment and rank junior to promotee already selected against the promotion quota of the same year. In case of 100% direct recruitment, the absorbee shall rank senior to direct recruit but in case of 100% promotion quota, the regular promotee will rank senior to absorbee.

(ii) Amendment in Regulation 14(2):

The existing Regulation 14(2) shall be replaced as under:

The service rendered by such person prior to absorption in the Commission in the parent Department/Organisation shall be counted as continuous service for the purposes of pay fixation, ACP. No leave balance of leave earned under parent organisation shall be carried forward but the leave availed, such as maternity leave, parental leave, child adoption leave, child care leave, study leave, etc., availed during the service rendered under parent organisation shall be treated as availed under RERC. The experience of the post under parent organisation shall be counted for promotion only if such experience does not involve supersession of any senior official, except when such supersession was either due to want of prescribed academic

and other qualifications, unfitness or non-selection by merit or the default of the senior official concerned.”

By Order of the Commissio

B.K. Dosi,

Secretary

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।